विवरण

31.12.1999 **को भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्वाधीन गोदामों की संख्या और उनकी भंडारण क्षमता**

क्रम सं0	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्षमता (हजार टन में)
1.	मुम्बई सिटी	जी0आई0सी0	20.94
	बोरीवल्ली	सिवरी	27.36
	बोरीवल्ली	वडाला	39.00
		जनरल मोटर्स	14.30
		(एफएसडी)	180.06
		(सिलो)	104.00
2.	थाणे	भिवंडी	10.01
3.	रायगढ़	पनवल	91.67
4.	मनमाड	(एफएसडी)	330.00
	मनमाड	(सिलो)	84.00
	मनमाड़		
5.	भंडारा	गोंदिया	30.00
6.	मनमाड	नागपुर	74.77
7.	वर्धा	वर्धा	105.00
8.	अहमदनगर	अहमदनगर	5.00
9.	पुणे	पूना	29.00
10.	शोलापुर	शोलापुर	22.00
11.	रत्नगिरि	रत्नगिरि	10.00
		जोड़ :	1177.11

Shortage of food in Andaman and Nicobar Islands

1125. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the unprecedented shortage of food being faced by the tribal communities of the Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, what measure have been taken by Government to meet the acute food deficiency in the island to save the tribal communities from starvation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) No, Sir. No reports have been received about shortage of food being faced by the tribal communities of the Andaman and Nicobar Islands.

(b) Does not arise.

New PDS for people below Poverty Line

1126. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating a new Public Distribution System (PDS) for the consumers below poverty line; and

(b) whether it is a fact that Government are attempting to reduce staggering fiscal deficit by a steep hike in PDS prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) No, Sir. The Government have already introduced (with effect from June, 1997) the Targeted Public Distribution System (TPDS) under which the consumers below poverty line (BPL) are entitled to get 10 kg. of foodgrains per month per family at specially subsidised prices. TPDS is in operation now in all the States and Union Territories except the State of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Lakshadweep.

(b) With a view to contain food subsidy to manageable level, the Central Issue Prices (CIP) of wheat and rice under TPDS have been revised upward for families above poverty line (APL) only with effect from 29.1.1999 as shown below:

(Rs. per kg.)

Commodity	CIP for APL	
	Before 29.1.1999	From 29.1.1999
Wheat	4.5	6.50
Rice-Common	0	7.00*
Rice-Grade 'A'	5.5	9.05

*For APL families, applicable only to J&K, Himachal Pradesh and hilly areas of North Eastern States including Sikkim and Uttar Pradesh.

The retail issue price of sugar under PDS has also been increased with effect from 15.2.1999 from Rs. 11.40 to Rs. 12.00 per kg.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त गेहूं और चावल की बिक्री

1127. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री राज मोहिन्दर सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने अपने भंडार में से गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्रा को खुले बाजार में बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं और चावल की कितनी मात्रा को बेचे जाने का निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या इन खाद्यान्नों का बिक्री मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न अंचलों के लिए गेहूं और चावल का बिक्री मूल्य कितना-कितना निर्धारित किया गया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) अधीन खुले बाजार में चावल की बिक्री करने का कोई निर्णय नही लिया है किन्तु 40 लाख तक गेहूं की बिक्री करने का निर्णय किया है ।

(ग) और (घ) गेहूं कि बिक्री मूल्य जोनवार निर्धारित किया गया है । इस समय इस योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं का निर्गम मूल्य निम्नानुसार है:-

जोन का नाम	दर प्रति क्विंटल (रुपयों में)
उत्तरी जोन (मध्य प्रदेश राज्य सहित)	
दिल्ली	
हरियाणा	
हिमाचल प्रदेश	653/- रुपये
जम्मू और कश्मीर	
पंजाब	
राजस्थान	
उत्तर प्रदेश	
दक्षिण जोन	
आंध्र प्रदेश	
केरल	724/- रुपये